asked to look into the matter further and take necessary action.

11. Housing Branch, DDA has been requested to issue notices to the allottees to clear the dues to the Regd. Agencies.

Recommendations of working group for Rural Storage Centres

19. SHRI P. M. SAYEED:
SHRI NIHAR LASKAR:
SHRI A. R. BADRI NARAYAN:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether a detailed scheme based on the recommendations of the working group set up by Government for setting up rural storage centres has been formulated by Government;

(b) if so, what are the main points of the scheme;

(c) whether all its recommendations have been accepted; and

(d) if not, how many of them have been rejected?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) The scheme is still under consideration of the Government.

(c) The recommendations of the Working Group in their broad outlines have been accepted.

(d) Recommendations relating to capacity and number of godowns, pattern of assistance, agency of construction and operation have been slightly modified.

सरकारी आवास में रह रहे भूतपूर्व सदस्य/भूतपूर्व मंत्री

20. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व संसद् सदस्यों/भूतपूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं जो 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1979 तक सरकारी बंगलों, मकानों और फ्लेटों में रहे और वह अवधि तथा तारीख भी बताई जाये जिस अवधि तथा तारीख तक वे उस आवास में रहे अथवा अभी रह रहे हैं जिसमें वे संसद् से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद रहने के हकदार नहीं थे और यदि वे तब तक भी सदस्य अथवा मंत्री रहे तो उस आवास के लिए उनके द्वारा अदा किये जाने वाला किराया कितना था और उसके बाद उनसे वसूल की गई किराए की राशि कितनी थी और प्रत्येक मामले में उस आवास के लिए बाजार दर पर निर्धारित किराया क्या था ;

(ख) दिल्ली में भूतपूर्वक संसद् सदस्यों/मंत्रियों को रिहायशी आवास के आवंटन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा और लागू होने वाले नियम क्या हैं ; और

(ग) भूतपूर्व संसद् सदस्यों/मंत्रियों के कब्जे के मकान में काम करने वाले मालिकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाला व्यय कौन वहन करता है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) भूतपूर्व संसद् सदस्यों / भूतपूर्व मंत्रियों को वास आवंटित करने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है ।

फिर भी सदस्य न रहने की स्थिति में सरकारी वास को रखने की अनुज्ञेय अवधि एक मास है तथा किसी सदस्य की मृत्यु होने के मामलें में अनुमेय अवधि दो मास है जिसकी शर्तें वही होती हैं जो उपर्युक्त घटनाओं में से किसी भी घटना के होने के तुरन्त पहले लागू थीं ।

मंत्रियों के सम्बन्ध में किराया मुक्त आधार पर वास को रखने की अनुमेय अवधि एक मास है जो उस तारीख से गिनी जाती है जिस तारीख को वह मंत्री पद से हट जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है ।

(ग) प्रारम्भ में व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है और एफ० आर० 45-ए० के अन्तर्गत सामान्य किराए की अपेक्षा अन्य दर पर किराया देने वाले दखलकारों से वसूल किया जाता है ।

Shortage of construction Material

21. SHRI CHHATRA BAHADUR CHHETRI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there is acute shortage of construction material for the construction of small scale units in the State of Sikkim;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) what steps Government is taking to provide the construction material to the State?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (c). As the C.P.W.D. is not concerned with the construction of small scale units in the State of Sikkim, the Ministry of Works and Housing has no information. The Government of Sikkim has got its own Public Works Department.

Provision of Drinking Water to Villages

22. SHRI K. T. KOSALRAM:
DR. BIJOY MONDAL:
SHRI DURGA CHAND:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the details of the scheme for providing water to all 1.53 lakhs 'problem' villages in the country having no source of potable water within one-and-half kilometers.

(b) in how many States this scheme is in operation and the financial implications thereof; and

(c) when this scheme will be extended to all over the country?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The Programme launched from 1977-78 known as the 'Centrally-sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme' is intended to cover rapidly the 1.13 lakh problem villages remaining to be covered out of the total of 1.53 such villages. Under the Programme grant-in-aid is given to States/Union Territories in order to accelerate progress by supplementing the State'/Union Territories Plan resources under the Minimum Needs Programme.

The types of schemes financed are generally bore well with hand pump connections and in some cases piped water supply for bigger villages or group of villages. The emphasis is on extensive coverage per unit of input and for this reason low-cost schemes are advocated.

(b) and (c). The Scheme covers the entire country in as much as tne 1.13 lakh problem villages are spread all over the country. In financial terms the grant-in-aid provided from 1977-78 are as under:—

1977-78	Rs. 38.20 crores.
1978-79	Rs. 60 crores.
1979-80	Rs. 80 crores (provided; to be released during the course of the current year).

मंजूरी के लिए विचाराधीन पड़ी राजस्थान की सिंचाई योजनायें

23. **श्री दौलतराम सारण** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की उन सिंचाई योजनाओं के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़ी हैं और वे किन तारीखों से विचाराधीन पड़ी हैं;